coffee production in 1995-96 compared to 1994-95. The actual production figures are:—

(tonnes)

	1994-95	1995-96
Karnataka	1,23,050	1,58,900
Kerala	39,000	45,000
Tamil Nadu	15,870	17,500

(c) In order to boost the production of coffee Board besides operating several plan projects and developmental activities like intensive cultivation, replanting programme and quality improvement programme has also been providing the necessary support in the form of (a) agricultural research (b) extension (c) arrangment of credit and finance and (d) other necessary backup support like supply of seed coffee for planting purpose.

खाद्यान्नों के खरीद मूल्य

2240. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खाद्यान्नों के खरीद मूल्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या आधार/मानदण्ड अपनाया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) सरकार ने 1.10.1996 से खरीफ विपणन मौसम, 1996-97 के लिए धान और खरीफ के मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है।

1995-96 के मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 1996-97 के मौसम के लिए धान और मोटे अनाजों के बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	1996-97	1995-96
धान:		
साधारण	380/- रु०	360/- रु०
बढ़िया	395/- रु०	375/- रु०
उत्तम	415/- रु०	395/- रु०
मोटे अनाज:		
ज्वार/बाजरा/रागी	310/- रु०	300/- रु०
मक्का	320/- रु०	310/- रु०

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित किए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय उत्पादन लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करता है।

Stabilisation fund for Bidi workers

2241. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether a stabilisation fund has been developed to help bidi workers to switch to other kinds of employment due to restrictive anti-tobacco legislation;

(b) if so, the details thereof;

(c) quantum of funds earmarked; and

(d) whether WHO has offered funds for this purpose?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Proposed restructuring at the Ninth Session of UNCTAD

2242. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the nature of restructuring proposed for the organisation at the ninth